an annual income of not more than Rs. 6500/-.

Since the objective of these institutions is to serve weaker sections of the rural community, it is felt necessary to relate source of recruitment as also the pay and allowances of the employees etc. to the environment in which these banks are working so that they are able to develop a local, low cost profile.

For this purpose it has been specifically laid down in section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 that the remuneration of the officers and other employees of such banks would be determined by the Central Government having due regard to the salary structure of the employees of the State Government (or of a local authority) of comparable level and status. The basic premise of the scheme of setting up Regional Rural Banks will be knocked out if the pay structure of the employees of the regional rural banks is to be on par with that of the commercial banks.

Effectiveness of S.T.C.

936. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Nylon yarn spinners have been thwarting the attempts of the State Trading Corporation to expand its basket of foreign suppliers of caprolactum, as per news-item appeared in the 'Indian Express' New Delhi of 13 January, 1984 under the caption 'Business Notes'; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure that the effectiveness of the State Trading Corporation is not reduced when such presures are being placed on it by influential industry lobbies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The Nylon yarn spinners who are the actual users of caprolactum have been reluctant to accept the caprolactum from new/additional sources on the plea that material offered by such sources has not been used and tried in past by them. It has, however, been possible for STC to add, during the course of the year, two new and additional sources of supply for this item.

(b) Efforts by STC are continuing to further enlarge the supply base for caprolactum.

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

937. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को क, ख और ग तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित उनके मन्त्रालय, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) की क्रियान्वित की प्रतिशतता का राज्यवार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उक्त सभी 14 मुद्दों को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक 1, 2 और 3 में विवरणों में दी गई है। सभा-पटल पर रखा गया। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 7786/84]। इस सम्बन्ध में आंकड़े रेल सुरक्षा आयोग द्वारा वर्ष 1981-82 में और वायुदूत द्वारा वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 में नहीं रखे गए थे। तथापि वे अब ये आंकड़े रख रहे हैं। इण्डियन एयरलाइन्स के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यद्यपि उक्त संगठन में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों को सामान्य रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, परन्तु उसमें अपेक्षित आंकड़े नहीं रखे गए हैं। उक्त संगठन को ऐसा करने के निदेश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों के कार्यान्वियन में पिछले वर्षों में पर्याप्त सुधार और वृद्धि हुई है। प्रशिक्षित हिन्दी कर्मचारियों की कमी के कारण राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कुछ कमी रही है। हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की प्रगति की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कार्यान्वयन की स्थिति का विभिन्न संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों से मन्त्रालय में प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए भी प्रबोधन किया जाता है, इन रिपोर्टों की जांच की जाती है और उनमें रही हुई कमियों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए सम्बन्धित कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है। मंत्रालय और सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और नियमों के मुख्यालयों में राजभाषा निरीक्षण दल बनाए गए हैं। ये दल राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए अपने कार्यालयों का आवधिक रूप से निरीक्षण करते हैं।

Giving Full Excise Duty Exemption to Cross Reeled Hank Yarn

938. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have takan up with the Finance Ministry the question of giving full excise duty exemption to cross reeled hank yarn used by the State Handloom Co-operative Agency Societies or State Handloom Development Corporations; and

(b) if so, the details regarding the demand and policy decision of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : (a) Yes, Sir.

(b) The demand for cross reeled hank yarn comes mostly from Maharashtra, U.P. and some part of West Bengal. With effect from 1-3-1984 the basic excise duty on such yarn has been reduiced.